भारत सरकार

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1388

27.11.2019 को उत्तर देने के लिए

जीडीपी में गिरावट

1388. श्रीमती नुसरत जहां रूही:
श्री थोमस चाज़िकाडन:
श्री एम. बदरूद्दीन अज़मल:

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर विगत कई महीनों के दौरान दिन-प्रतिदिन धीमी हो रही है;
(ख) यदि हां, तो क्या सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर छह साल में अपने निचले स्तर पर पहुंच कर पांच प्रतिशत से कम हो गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) जीडीपी वृद्धि दर को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं;
(घ) विगत पांच वर्षों के दौरान जीडीपी वृद्धि दर का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
(ड.) देश की जीडीपी दर की गिरावट के रुख से कब तक बाहर आने की संभावना है?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) [राव इंद्रजीत सिंह]

(क) और (ख): वर्ष 2014-15 से 2019-20 की प्रथम तिमाही तक स्थिर (2011-12) मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तिमाही वृद्धि दरें निम्नानुसार हैं:

वर्ष	तिमाही वृद्धि दर (% में)			
	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4
2014-15	8.0	8.7	5.9	7.1
2015-16	7.6	8.0	7.2	9.1
2016-17	9.4	8.9	7.5	7.0
2017-18	6.0	6.8	7.7	8.1
2018-19	8.0	7.0	6.6	5.8
2019-20	5.0	-	-	-

(ग) से (ड.): जीडीपी में बढ़ोतरी के उद्देश्य से सरकार विभिन्न उपाय करती रही है। वर्ष 2016 में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को पेश किया जो देश की वित्तीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्ष 2017 में वस्तु एवं सेवा कर का क्रियान्वयन देश में व्यापार की

सुगमता में सुधार के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण उपाय है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम विश्व स्तरीय वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए स्वदेशी क्षमता को बढ़ावा देने के लिए की गई एक प्रमुख पहल है। निरंतर उदारीकरण के फलस्वरूप देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। हाल ही में, सरकार ने निवेश गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट कर की दर को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है। विशेषकर, नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट कर को 15 प्रतिशत तक कम कर दिया है, जो कि विश्व के न्यूनतम दरों में से एक है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2019 के दौरान रेपो दर में की गई 135 आधारी बिंदुओं की कटौती का पूरक है तथा बैंकों को निवेशकों के लिए पूंजी लागत में कमी लाने के उद्देश्य से उनकी उधारी दरों को बाह्य बेंचमार्कों से जोड़ने के लिए अधिदेशित करता है। सरकार ने रुकी हुई आवासीय परियोजनाओं के लिए 25000 करोड़ रुपये का रियल्टी फंड अनुमोदित किया है। सरकार ने सभी किसानों को सम्मिलित करते हुए प्रधानमंत्री किसान योजना का विस्तार किया है, जो ग्रामीण उपभोग को बढ़ावा देगा। सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यातकों को प्रोत्साहन देने मर्चेन्डाइज़ एक्सपोर्टस फ्रॉम इंडिया स्कीम (एमईआईएस) को प्रतिस्थापित करते हुए निर्यात संवर्धन के उद्देश्य के लिए करों एवं शुल्कों की प्रतिपूर्ति संबंधी योजना का विस्तार, जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट की पूर्णत: स्वचालित इलैक्ट्रॉनिक धन वापसी और निर्यात क्रेडिट के लिए संशोधित प्राथमिकता क्षेत्र उधारी मानदंडों के साथ-साथ अनेक उपाय किए हैं ।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2019-20 में अगले पांच वर्षों में अवसंरचना ढांचे में 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने की मंशा सहित राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम के पुनर्गठन के द्वारा अवसंरचना विकास पर बल दिए जाने का प्रावधान है। पारंपरिक उद्योगों के स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और अधिक उत्पादकारी, लाभदायक और सक्षम बनाने के उद्देश्य से क्लस्टर आधारित विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए पारम्परिक उद्योगों के उन्नयन और पुनरोद्धार हेतु निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) शुरू की गई है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्थिर (2011-12) मूल्यों पर वार्षिक जीडीपी वृद्धि दरें निम्नलिखित हैं:

वर्ष	जीडीपी वृद्धि दर (% में)
2014-15	7.4
2015-16	8.0
2016-17	8.2
2017-18	7.2
2018-19 (अ.अ.)	6.8

अ.अ.-अनंतिम अनुमान

सरकार आर्थिक बढ़ोतरी को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय कर रही है। इसके अतिरिक्त, आईएमएफ तथा अन्य बहुपक्षीय संगठनों द्वारा मूल्यांकन निरंतर भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दर्शा रही है।

*****